कच्चे तेल के मूल्यों में कमी

*28. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1991 से जनवरी, 1992 के बीच अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का औसत मूल कितना था ;

(ग) क्या सरकार ने मूल्यों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिये जाने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव दोनों ही नीचे और ऊपर की ओर हुआ ।

(ख) दुबई क्रूड के लिये औसत प्रकाशित स्थल मूल्य, दिसम्बर, 1991 के दौरान 15.22 अमेरिकी डालर प्रति बैरल और जनवरी, 1992 के दौरान 15.30 अमेरिकी डालर प्रति बैरल था ।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर समय-समय पर निर्धारित किया जाता है और उनमें परिवर्तन केवल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जाता है ।

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

*29. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और अप्रैल, 1991 तक देश में कितनी मात्रा में कच्चे तेल के भंडार उपलब्ध थे;

(ग) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के दौरान अलग-अलग कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन कितन-कितना हुआ;

(घ) क्या सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन क्रमश: 32.06, 34.69 और 33.00 मिलियन टन था । अब निर्धारित वर्ष 1991-92 का लक्ष्यांकित उत्पादन 31.8 मिलियन टन का है । शेष वसूली योग्य भंडार लगभग 800 मि० टन का है । कई तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है ताकि देश में ही कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की जा सके ।

Protection of Ozone Layer

*30. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a constant threat to the atmospheric ozone layer due to industrial Pollutants:

(b) if so, what steps have been taken by Government at national and international level to ban the production of pollutants affecting ozone layer in the atmosphere;

(c) whether any research work is being done by the Central Government in the direction of protection of ozone layer; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) There is scientific evidence that certain gases containing chlorine, bromine and fluorine, collectively called Chloro-fluorocarbons (CFCs) and halons lead to depletion of the ozone layer in the stratosphere, specially over the polar regions.

(b) to (d) At the international level the major initiative was taken by the adoption of the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer in March 1985, which came into force in September, 1988. The Covention provides a general framework for addressing the ozone problem at the international level through coordinated research and exchange of information. This Convention was followed by the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, which was adopted in September, 1987. This Protocol, which came into force in January, 1989, lays down a time-table for stabilisation/reduction in the pro-duction and consumption of certain kids of CFCs and Hilons. Copies of the Vienna Convention and the Montreal Protocol are placed in the Parliament Library for reference.

India is a party to the Vienna Convention. Further, Government have set-up a Task Force to formulate a national strategy for the phasing out of ozone depleting substances and for adoption of substitute substances/technologies, including R&D efforts in the country.

Indian research and data collection about stratospheric ozone goes back to many decades and is spread over many institutions and agencies. A considerable amount of data about ozone is available from the studies carried out under the Indian Middle Atmosphere Programme. The India Meteoiotogical Department has a network of itzone stations and total ozone is measured at five stations. Measre-ments of vertical distribution of ozone are made at * three stations. Continuous recording of surface ozone amount is made at six stations.

The Council for Scientific and Industrial Research through its network of laboratories is engaged in R&D work relating to substitute for ozone depleting substances.

मलेरिया-उन्मूलन

*31. श्री लक्खी राम अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मलेरिया-उन्मूलन के लिये कोई दीर्घ-कालिक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां तो इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में मलेरिया-उन्मूलन के लिये इस योजना के अन्तर्गत सरकार किस प्रकार सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 1977 में मलेरिया नियंत्रण के लिये एक संशोधित कार्य योजना आरम्भ की । मलेरिया की घटनाओं में कमी लाने में सफलता मिली है । वर्ष 1976 में मलेरिया के 6.47 मिलियन रोगी थे जिनकी संख्या 1990 में घट कर 1.9 मिलियम रह गई । बहरहाल, देश में मलेरिया के रोगियों की संख्या अब लगभग 2 मिलियन प्रतिवर्ष पर स्थिर है ।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान मलेरिया की घटनाओं में कमी आने का कोई खास रुझान नहीं दिखाई पड़ा है । अब